

विभाग, बिहार, पटना ने ई.-शासन के मानक तैयार करने/अपनाने के उद्देश्य राष्ट्रीय ई.-शासन योजना (NeGP) के अन्तर्गत राज्य स्तरीय ई.-शासन शीर्ष समिति (SeGP Apex Committee) का गठन किया है।

विभिन्न भाषाओं में सूचना की उपलब्धता की कमी के कारण सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में धीमी प्रगति हो रही है और I.C.T. का लाभ सामान्य जनता के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा भाषा प्रौद्योगिकी का स्थानीयकरण पर ध्यान मानकीकरण के अन्तर्गत दिया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि राज्य सरकार भी इस ओर अपना ध्यान आकृष्ट करें।

विदित हो कि भारत सरकार के द्वारा यूनिकोड-5.1.0 के अक्षर कोडीकरण मानक के रूप में अनुमोदित कर दिया गया है, जिसके तहत बहुभाषी पाठ के प्रस्तुतीकरण के लिए पूरे विश्व में व्यापक स्वीकृति प्राप्त है और भारतीय भाषाओं का भी समर्थन करता है, और इसके साथ-साथ यह संविधान द्वारा स्वीकृत सभी भाषाओं के लिए अनुप्रयोगों के स्थानीयकरण को सरल बनाता है।

अतः सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के तर्ज पर राज्य सरकार भी यूनिकोड-5.1.0 तथा इसके भावी संस्करणों को इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से ई.-शासन अनुप्रयोगों के मामले में मानक के रूप में अधिसूचित करता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरुण कुमार सिंह, प्रधान सचिव।

23 मार्च 2010

सू० प्रा०-34/2010-340—सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की तरह राज्य सरकार राष्ट्रीय ई.-शासन योजना (NeGP) का परिवर्तन कर रहा है, जिसका उद्देश्य शासन एवं सांस्थानिक तंत्र तैयार करना तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों के स्तर पर विभिन्न मिशन मोड का कार्यान्वयन करना है।

विदित हो कि राष्ट्रीय ई.-शासन योजना (NeGP) के अन्तर्गत राज्य सरकार भारत सरकार की तरह किसी भी प्रकार के प्रौद्योगिकीय अवरोध से बचने के लिए मुक्त मानकों के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है।

आप अवगत हैं कि ई.-शासन में मानक एक उच्च प्राथमिकता वाला कार्य-कलाप है, जिससे सूचना को आपस में बाँटने तथा विभिन्न ई.-शासन अनुप्रयोगों में डेटा की अविच्छिन्न अन्तर-प्रचालनीयता का सुनिश्चय होता है। सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना ने ई.-शासन के मानक तैयार करने/अपनाने के उद्देश्य राष्ट्रीय ई.-शासन योजना (NeGP) के अन्तर्गत राज्य स्तरीय ई.-शासन शीर्ष समिति (SeGP Apex Committee) का गठन किया है।

विभिन्न भाषाओं में सूचना की उपलब्धता की कमी के कारण सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में धीमी प्रगति हो रही है और I.C.T. का लाभ सामान्य जनता के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा भाषा प्रौद्योगिकी का स्थानीयकरण पर ध्यान मानकीकरण के अन्तर्गत दिया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि राज्य सरकार भी इस ओर अपना ध्यान आकृष्ट करें।

विदित हो कि भारत सरकार के द्वारा आईएसओ/आईईसी-14496-ओएफएफ (मुक्त फोन्ट प्रारूप) को फोन्ट के रूप में अनुमोदित कर दिया गया है, एक अन्तर्राष्ट्रीय मानक पर आधारित है तथा डेटा भण्डारण के लिए यूनिकोड का अनुपालन करता है। इससे विभिन्न अनुप्रयोगों तथा प्लेटफॉर्मों पर डेटा को ले जाना सुनिश्चित होता है।

अतः सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के तर्ज पर राज्य सरकार भी आईएसओ/आईईसी-14496-ओएफएफ (मुक्त फोन्ट प्रारूप) को इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से ई.-शासन अनुप्रयोगों के मामले में सभी 22 भारतीय भाषाओं के लिए मानक फोन्ट के रूप में अधिसूचित करता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरुण कुमार सिंह, प्रधान सचिव।

वित्त विभाग

अधिसूचनाएं

18 जून 2010

सं० अ०पा०-95/2008-538—राज्य सरकार ने Bihar Capacity Building Technical Assistance (BCBTA) के लिए DFID विश्व बैंक Trust Fund की सहायता से एक नये Procurement Manual एवं Standard Bidding Document बनाने का निर्णय लिया है। इस क्रम में Terms of Reference के आलोक में प्रधान सचिव, वित्त की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-